सत्यमेव जयते

श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधानसभा अधिवेशन

फाल्गुन–चैत्र, विक्रम संवत–2081, शक 1947 भोपाल, सोमवार 10 मार्च, 2025

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

- सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
- मध्यप्रदेश की षोड्श (16वीं) विधानसभा के पंचम सत्र में उपस्थित होकर मुझे सदन को संबोधित करते हुए हृदय से प्रसन्नता हो रही है। इस सदन के सदस्य लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं। मध्यप्रदेश की विधानसभा ने श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं को स्थापित किया है। जनकल्याण के विषयों पर सजग रहकर चर्चा की दृष्टि से भी मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य आदर्श भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं। वास्तव में सदन के सदस्यों का यह गुण हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाता है।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समावेशी विकास के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर लिए गए नीतिगत निर्णयों, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से हमारे राष्ट्रवासियों के हित का संवर्धन निरंतर हो रहा है। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भारत की तीव्र प्रगति में मध्यप्रदेश अधिक से अधिक सहयोग करते हुए सक्रिय सहभागिता के लिए तत्पर है।
- मेरी सरकार ने "संकल्प पत्र" 2023 में मध्यप्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो संकल्प व्यक्त किया उसे पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है।

- माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में सहयोग देते हुये मध्यप्रदेश ने भी विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना की है।
- सदन को यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश में महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की पहल हुई है। यह परियोजनाएँ मध्यप्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य करेंगी। जहाँ केन-बेतवा परियोजना प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के 10 जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा बढ़ाने में सहायक होगी, वहीं पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना 11 जिलों को लाभान्वित करेगी। मध्यप्रदेश के जिलों के साथ ही केन-बेतवा परियोजना से जहाँ उत्तरप्रदेश का बड़ा इलाका लाभान्वित होगा, वहीं पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से राजस्थान को भी लाभ मिलेगा। यह सिलसिला यहीं नहीं थमा है। तीसरी अंतर्राज्यीय परियोजना-ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में संयुक्त रूप से किए जाने की दिशा में दोनों प्रदेशों में आवश्यक प्रक्रिया चल रही है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। राज्य के भीतर भी गंभीर नदी तथा कान्ह नदी को जोड़ने के कार्य की स्वीकृति के बाद अन्य नदियों

को जोड़ने के संबंध में तकनीकी परीक्षण उपरांत कार्य योजना बनाने का काम प्रारंभ किया जा रहा है।

- हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने (GYAN) ज्ञान का मंत्र दिया है। ज्ञान का अर्थ है- गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चार वर्गों के कल्याण के लिए मध्यप्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार ने चार मिशन, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ कर दिए हैं।

- मेरी सरकार ने बहुआयामी गरीबी का सूचकांक कम करने के उद्देश्य से गरीब कल्याण मिशन प्रारंभ किया है। मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुए उनकी आय को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। गरीब कल्याण मिशन मुख्यतः तीन घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इण्डेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है।

- मेरी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा-उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया है। समस्त 54 विभागों में संचालित युवाओं के हित और उनसे संबंधित योजनाओं और

कार्यक्रमों में समन्वय करते हुए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उनकी क्षमता संवर्धन के लिए उद्यमिता में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना तथा युवाओं की ऊर्जा का, देश और प्रदेश हित में उपयोग सुनिश्चित करना युवा शक्ति मिशन का उद्देश्य है।

- मेरी सरकार ने महिलाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास एवं सुरक्षा, महिलाओं तथा बालिकाओं तक विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना, महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन और समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए पुरुषों में संवेदनशीलता बढ़ाने वाली जागरूकता विकसित किया जाना शामिल है।
- किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे। किसानों की उपज की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकी साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। मेरी सरकार कृषि

को लाभदायी व्यवसाय बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित कई योजनाएँ किसानों को लाभान्वित कर रही हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रदाय की जाती है। वर्ष 2024-25 की तीसरी किश्त के रूप में किसानों को 1 हजार 624 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण हुआ है। योजना में गत वर्ष किसानों को 4 हजार करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। किसानों को गेहूँ के समर्थन मूल्य 2425 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त, 175 रूपये का बोनस देते हुए प्रति क्विंटल 2600 रूपये देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी का कार्य संपूर्ण राज्य में 15 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को उपार्जन की प्रक्रिया पूर्ण करने पर राज्य सरकार ने 4 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रति हेक्टेयर के मान से देने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम है। मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार किसानों से 4 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का निर्णय लिया गया। मेरी सरकार ने

एक महत्वपूर्ण निर्णय रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का लिया था। योजना के अंतर्गत कोदो-कुटकी के उपार्जन के लिए महासंघ का गठन किया गया है। ऐसे अन्न उत्पादक किसानों को 3 हजार 900 रूपए प्रति हेक्टेयर के मान से डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में राशि देने का प्रबंध किया गया। जैविक, उन्नत और प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हैं। प्रत्येक पैक्स में पीएम किसान समृद्धि केन्द्र खुल रहे हैं। मेरी सरकार मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित कर रही है। उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर करने एवं मध्यप्रदेश को उद्यानिकी क्षेत्रों में अग्रणी बनाने का संकल्प लिया गया है। मेरी सरकार अगले तीन वर्ष में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध करवाकर, किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली खरीद कर उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा। साथ ही किसानों को अब 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

- प्रदेश के सतत विकास एवं कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उददेश्य से नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं जल

संसाधन विभाग की सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर को वर्ष 2028-29 तक बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक विकसित किया जाएगा। माइक्रो सिंचाई में प्रदेश, देश में अग्रणी है। दिसम्बर 2024 तक माइक्रो सिंचाई परियोजना से 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचित किया गया है।

- प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की पहल हुई है। प्रदेश के अधिक से अधिक गाँवों के लिए दुग्ध समितियों के गठन का लक्ष्य है। साँची ब्रांड को मजबूत किया जा रहा है। मध्यप्रदेश को डेयरी कैपिटल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। प्रदेश में अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं की गौशालाएँ भी बड़ी संख्या में संचालित हैं। मेरी सरकार इन गौशालाओं के संचालन में सहयोग दे रही है। गौवंश के चारे भूसे के लिए 20 रुपये की आहार राशि को बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिवस के मान से करने का निर्णय लिया जाना प्रक्रियारत है। प्रदेश में मत्स्य पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू है। वर्ष 2024-25 में 1 लाख 30 हजार मत्स्य पालकों का नि:शुल्क दुघर्टना बीमा करवाया गया है। प्रदेश में लगभग साढ़े चार लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में मत्स्य पालन हो रहा है। मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए गए हैं।

- प्रदेश में शिक्षा व्यवस्थाएँ बेहतर बनाई जा रहीं हैं। मेरी सरकार ने प्रदेश के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी प्रदान की है। प्रदेश के 89 हजार 710 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए उनके खातों में 224 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई। प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाई में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर स्कूल शिक्षा विभाग की अभिनव योजना में इस वर्ष प्रदेश के 7 हजार 832 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नि:शुल्क ई-स्कूटी प्रदान की गई। प्रदेश में तीन नवीन शासकीय विश्वविद्यालयों- क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना हुई है। मेरी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये है। इस तरह के कुल 55 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। मेरी सरकार ने स्कूल शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लगभग 780 पी.एम. श्री स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में 355 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि वितरित की जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 2 हजार 383 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत 4 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश के 4

संभागीय मुख्यालयों यथा सागर, जबलपुर, उज्जैन एवं रीवा में स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का उन्नयन कर मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। आई.आई.टी., दिल्ली के सहयोग से राज्य के 3 महाविद्यालयों में 4 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' भी स्थापित किए गए हैं। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

- प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिए निरंतर नए मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 17 शासकीय और 13 निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले एक साल में 3 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करवाए हैं। मेरी सरकार प्रदेश में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 12 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के समस्त जिलों में आधुनिक तकनीक एवं उपकरणयुक्त एक हजार 2 संजीवनी 108 एम्बुलेंस तथा एक हजार 59 जननी एम्बुलेंस वाहनों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में कुल 65 हेमोडायलिसिस इकाइयाँ संचालित हैं। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 21 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 38 लाख से अधिक परिवारों को नि:शुल्क

उपचार मिला है। प्रदेश में पीएमश्री एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है। यह सेवा आपातकाल में दूरस्थ स्थानों से गंभीर रोगियों और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को बड़े चिकित्सा संस्थानों तक उपचार के लिए ले जाने में सहायक सिद्ध हुई है। प्रदेश में लगभग डेढ़ करोड़ नागरिकों को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। मेरी सरकार प्रदेश में नए 11 आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारंभ करेगी और 108 आयुष औषधालय भवन निर्मित किए जाएंगे। जनजातीय बहुल बालाघाट जिले में औषधियों हेतु शोध केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 36 लाख ग्रामीण आवास का निर्माण पूर्ण किया गया है व 13 लाख आवास का निर्माण प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से 11 लाख 89 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पीएम जनमन योजना मध्यप्रदेश के 24 जिलों में क्रियान्वित है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजनांतर्गत अभी तक एक लाख 83 हजार परिवारों का सर्वे हुआ है। एक लाख 68 हजार आवास स्वीकृत किये गये तथा 49 हजार 292 आवास पूर्ण किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत आवासों की पूर्णता में मध्यप्रदेश देश में

प्रथम स्थान पर है। डेढ़ लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय और 700 से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसर इस वर्ष बनाए गए हैं। राज्य आजीविका फोरम के अंतर्गत गाँव के निर्धन परिवारों की महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस वर्ष 3 लाख से अधिक परिवारों को कृषि और पशुपालन आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। प्रदेश में 3 लाख 17 हजार दीदियों को लखपति बनाया गया है। वृंदावन ग्राम योजना में प्रदेश के 313 विकासखंड में एक-एक ग्राम वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित होगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में प्रदेश के 45 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभांवित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्तमान वित्त वर्ष में 124 किलोमीटर लंबाई की 66 सड़कों का निर्माण हो रहा है।

शहरों के विकास के लिए अनेक कार्य हो रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत नगरीय निकायों में वृहद स्तर पर कार्य हो रहा है। प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में 7 राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। इंदौर निरंतर देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव प्राप्त कर रहा है। खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए शहरों में लगभग 6 लाख परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय और 22 हजार से अधिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। अमृत 2.0 में प्रदेश के 413 नगरीय निकायों और 5 कैंटोनमेंट क्षेत्र में

जल प्रदाय से लगभग 28 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रथम चरण में 8 लाख 33 हजार आवास बनाकर मध्यप्रदेश, देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में आगामी 5 वर्ष में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना में 5 हजार 718 करोड़ के 626 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना में 86 हजार से अधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार कार्यक्रम का लाभ मिला है। दस लाख से अधिक शहरी पथ विक्रताओं को लघु व्यवसाय के लिए स्थान उपलब्ध करवाया गया। पीएम स्वनिधि योजना में 13 लाख से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण दिलवाकर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश में 124 नगरीय निकाय में 191 से अधिक रसोई केन्द्र संचालित कर निर्धन परिवारों के लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने का प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास में 1640 करोड़ के 748 कार्य करवाए जा रहे हैं। कायाकल्प योजना में शहरों में 1263 किलोमीटर की उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण का कार्य मंजूर किया गया है। प्रदेश के 413 नगरों में गीता भवन बनाए जाएंगे, जो वाचनालय सुविधा के साथ रचनात्मक गतिविधियों के केन्द्र बनेंगे।

- मेरी सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के लगभग ढाई लाख विद्यार्थियों को 275 करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई। छात्रावास योजना में प्रदेश में 1913 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रावास संचालन के लिए 125 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान रखा गया है। मेरी सरकार द्वारा पूज्य संत रविदास जी की स्मृति में प्रदेश के 30 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संत रविदास स्मारक सह सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। सागर के निकट संत रविदास मंदिर का कार्य प्रगति पर है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का शुभारम्भ 15 नवंबर 2023 को किया। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 24 जिलों के बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। आहार अनुदान योजना के अंतर्गत सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को प्रतिमाह एक हजार पाँच सौ रुपये दिए जा रहे हैं। जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 2024-25 में कक्षा एक से दस तक के 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 48 करोड़ रूपये स्कूल शिक्षा विभाग के

माध्यम से वितरित किए गए। पोस्ट मैट्रिक एवं महाविद्यालीन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कक्षा 11 वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन एक लाख 92 हजार विद्यार्थियों को लगभग 348 करोड़ रूपये वितरित किए गए। मेरी सरकार ने धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान से लगभग एक करोड़ जनजातीय आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्य योजना में 90 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के भारत सरकार के लक्ष्य के विरुद्ध 97 लाख से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्क्रीनिंग के बाद जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी वितरित किए गए। जनजातीय समाज को इस रोग से इस बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है।

- मेरी सरकार विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय के विकास के लिए संकल्पित है। प्रदेश में इन समुदायों के अंतर्गत कुल 51 जातियां अधिसूचित हैं। इनमें से 14 अनुसूचित जाति, 10 पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में एवं 27 अनारक्षित वर्ग अर्थात सामान्य श्रेणी में सम्मलित हैं। इन वर्गों के विद्यार्थियों को वर्ष 2024-25 में राशि 3 करोड़ 62 लाख रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए गए।

- पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2024-25 में 885 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति वितरित की गई है। राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने पर प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2024-25 में 63 लाख रूपये से अधिक प्रदान किए गए।
- प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए राज्य शासन द्वारा "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना में प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख 21 हजार बहनों को प्रति हितग्राही एक हजार 250 रुपये के मान से प्रति माह लगभग एक हजार 500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कुल 52 लाख से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 लाख 75 हजार से अधिक हितग्राहियों को 264 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। प्रदेश की 12 हजार से अधिक मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन किया गया है। प्रदेश के बच्चों में कुपोषण निवारण तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए सहयोगी विभागों के समन्वय से "मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम" का क्रियान्वयन किया

जा रहा है। भारत सरकार से 24 हजार 662 आंगनवाड़ी केन्द्रों का सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्र के रूप में उन्नयन करने की स्वीकृति मिली है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 355 नए आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हुए हैं।

- प्रदेश में संस्कृति और साहित्य के संवर्धन, संरक्षण, विस्तार और विकास के लिए बहुआयामी कार्य किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में साधु-संतों को उज्जैन में आश्रमों के स्थायी निर्माण के लिए भूमि देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में विरासत के साथ विकास के विचार को महत्व देते हुए कई आध्यात्मिक लोक विकसित किए जा रहे हैं। ये स्थान भी पर्यटन विकास और अर्थव्यवस्था के सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम बनेंगे। प्रदेश में श्रीरामचन्द्र वनगमन पथ के प्रदेश से जुड़े आस्था स्थलों का चित्रांकन करवाकर एक दीर्घा तैयार की गई है। ऐसे स्थलों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस क्रम में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े विभिन्न तीर्थ-स्थलों जैसे सांदीपनी आश्रम, नारायणा (उज्जैन), जानापाव (इंदौर) एवं अमझेरा (धार) को जोड़कर श्रीकृष्ण पाथेय का निर्माण होगा। श्रीकृष्ण पाथेय न्यास का गठन किया गया है। भारत सरकार ने ओरछा और खजुराहो के होम-स्टे की व्यवस्थाओं को सराहनीय माना है और पुरस्कृत भी किया है।

सिंहस्थ-2028 को अलौकिक वैश्विक आयोजन बनाया जाएगा। उज्जैन में विश्व की पहली 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' स्थापित कर भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से करवाया गया। प्रदेश सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के विभिन्न आयामों को देश और विदेश के सामने लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया है। ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम का चरणबद्ध रूप से विकास किया जा रहा है। आदि गुरू शंकराचार्य जी के प्रतिमा स्थल और संपूर्ण क्षेत्र में सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय लिया गया है। उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक नगर पंचायत क्षेत्र, मैहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई और मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र, सलकनपुर, बरमान कलां, लिंगा, बरमान खुर्द, कुण्डलपुर और बांदकपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में शराबबंदी लागू होगी।

- मेरी सरकार ने नगरों के अधोसंरचना विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन (महानगर क्षेत्र) बनेंगे। इनमें एक महानगर क्षेत्र इंदौर-उज्जैन-देवास-धार को एकीकृत कर और दूसरा महानगर क्षेत्र प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा, राजगढ़ को एकीकृत कर विकसित किया जाएगा।

- गत वर्ष 76 नए ब्रिज और 5 हजार 190 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनी हैं। प्रदेश में कुल 9 हजार 315 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। महत्वपूर्ण और प्रमुख राजमार्गों को 4 लेन में बदलने का संकल्प है। प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में यातायात को सुगम बनाने के लिए 2 हजार 500 करोड़ की लागत से ऐलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 6 एक्सप्रेस-वे के कार्य किए जाएंगे। ये हैं- नर्मदा एक्सप्रेस-वे, विंध्य एक्सप्रेस-वे, मालवा-निमाड़ एक्सप्रेस-वे, अटल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और मध्यभारत एक्सप्रेस-वे। अगले पाँच वर्ष में प्रदेश में एक लाख किलोमीटर की सड़कें बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार से 16 हजार करोड़ से अधिक की लागत की इंदौर-मनमाड रेल्वे लाइन की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 8 हजार 631 ग्राम जुड़े हैं जिनकी लंबाई 19 हजार 472 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस वर्ष एक हजार किलोमीटर की सड़कों का निर्माण एवं 5 हजार 200 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। प्रदेश में सड़क परिवहन सुविधा के विस्तार के लिए पृथक कंपनी के माध्यम से शीघ्र लोक परिवहन बस सेवा का संचालन किया जाएगा।

- प्रदेश में बिजली के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। अटल गृह ज्योति योजना के तहत लगभग एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। अटल कृषि योजना के अंतर्गत 10 हार्सपॉवर तक के अनमीटर्ड स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रुपये प्रति हार्स पॉवर प्रतिवर्ष एवं 10 हार्सपॉवर से अधिक के अनमीटर्ड स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को एक हजार 500 रुपये प्रति हार्सपॉवर प्रतिवर्ष की दर से बिजली दी जा रही है। नवकरणीय ऊर्जा में मध्यप्रदेश ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। देश में पहली बार नवकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने की पहल हुई है। रीवा में सौर ऊर्जा पार्क देश के सबसे बड़े ऊर्जा पार्कों में से एक है। ओंकोरेश्वर में फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है। गत बारह वर्ष में मध्यप्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा में 14 गुना की वृद्धि हुई है। प्रदेश के कुल ऊर्जा उत्पादन में 30 प्रतिशत नवकरणीय ऊर्जा से होने वाला उत्पादन शामिल है। मुरैना में अपनी तरह का सोलर प्लस स्टोरेज पॉवर प्लांट बनने जा रहा है, जिसमें दिन के साथ रात में भी बिजली मिलेगी।
- युवाओं को विभिन्न स्टार्टअप के लिए सहायता दी जा रही है। खेल क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में 56 नए खेल स्टेडियम और प्रशिक्षण केन्द्र तैयार किए

जा रहे हैं। युवाओं की रचनात्मकता का प्रदेश के हित में उपयोग करने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है।

- चीता रहवास के विकास के लिए कूनो वनमण्डल का पुनर्गठन कर क्षेत्रफल में 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। घड़ियाल संवर्धन में मध्यप्रदेश में सराहनीय कार्य किया गया है। प्रदेश में रातापानी अभयारण्य को प्रदेश का आठवां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। प्रदेश में 9वां माधव नेशनल पार्क प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 35 लाख तेंदूपत्ता संग्रहकों का मानदेय 3 हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपये किया गया है।

- सदन को यह बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि हाल ही में भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री जी ने मध्यप्रदेश की ताकत और मध्यप्रदेश सरकार के प्रगति के प्रयासों की खुले हृदय से प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिखाया गया विश्वास हमें प्रेरित करता है। आप सभी अवगत भी होंगे कि मार्च 2024 में उज्जैन से शुरू हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से लेकर फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन तक मध्यप्रदेश में 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और इनके क्रियान्वयन का कार्य भी शुरू हो गया है।

उद्योगों के विकास से प्रदेश के युवाओं को भी बड़ी संख्या में रोज़गार प्राप्त कराने का महती उद्देश्य पूरा हो रहा है।

- मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश जन विश्वास विधेयक 2024 लागू करने का निर्णय लिया, इस विधेयक के माध्यम से आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुधार, उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों को विभिन्न व्यवसायों के संचालन की सुविधा, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन, व्यावसायिक दक्षता और नागरिकों का जीवन आसान बनाने के बहुआयामी लाभ दिलवाने की पहल की गई है। "ईंज ऑफ डूइंग बिजनेस" रैंकिंग में मध्यप्रदेश हमेशा से ही अग्रणी श्रेणी के राज्यों में शामिल रहा है। वर्ष 2024 में उद्योग क्षेत्र में मध्यप्रदेश को "टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज" के अंतर्गत सम्मानित किया गया। यही नहीं छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने में भी मध्यप्रदेश पुरस्कृत और सम्मानित हुआ है। कुटीर और ग्रामों से जुड़े उद्योगों के विकास का कार्य भी हो रहा है। मध्यप्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर 14 विभागों से संबंधित 54 सेवाएँ उपलब्ध हैं। औद्योगिक निवेश बढ़ाने एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोज़गार वर्ष घोषित किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन के लिए लागू 18 नवीन

नीतियों का शुभारंभ किया। प्रमुख रूप से उद्योग, एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक्स, स्टार्ट-अप, एनीमेशन, सेमी कंडक्टर, ड्रोन के उपयोग, पर्यटन, विमानन, स्वास्थ्य और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी इन प्रोत्साहनकारी नीतियां तथा निवेश संवर्धन नीतियों से प्रदेश में तेजी से निवेश बढ़ेगा। भोपाल में संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अत्यंत सफल रही।

- मेरी सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में साढ़े पाँच हजार से अधिक हितग्राहियों को पौने चार सौ करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया है। मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में स्टार्ट-अप प्रारंभ हो रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने 105 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। मध्यप्रदेश में सूचना प्रौघोगिकी, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, ड्रोन सेमीकन्डक्टर एवं ऑडियों विज्युवल क्षेत्र की कम्पनियों की निवेश के प्रति बढ़ती संभावनओं के दृष्टिगत राज्य ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर्स नीति 2025, मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025, मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2025, मध्यप्रदेश एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेंमिंग कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी नीति 2025 जारी की गई है। इन चारों नीतियों के प्रभावशील होने से प्रदेश में निवेश, नवाचार, आर्थिक विकास

और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

- प्रदेश के विकास में खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में कोयला, चूना-पत्थर, ताम्र अयस्क, मैंगनीज, आयरन और, बॉक्साइट एवं रॉक फास्फेट आदि प्रमुख खनिजों का दोहन किया जाता है। हीरे की उपलब्धता में प्रदेश का देश में एकाधिकार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ताम्र अयस्क एवं मैंगनीज के उत्पादन में प्रदेश पहले स्थान पर है। रॉक फास्फेट एवं चूना-पत्थर में दूसरा एवं कोयला के उत्पादन में चौथा स्थान है। आयरन ओर एवं बॉक्साइट के उत्पादन में प्रदेश का स्थान छठवां है। 2023-24 में प्रदेश में खनिजों से लक्ष्य के मुकाबले 105.96 प्रतिशत की आय हुई। भोपाल में अक्टूबर 2024 में दो दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजित की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नवाचारों से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश में माइनिंग क्षेत्र में नवाचार में सफलता मिली है। सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल के 2 ब्लॉक्स को नीलामी में रखा गया।
- प्रदेश में विमानन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट रीवा में प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की पहल पर सस्ती विमानन सेवा प्रारंभ की गई। ग्वालियर विमानतल के विकास एवं विस्तार के लिए राज्य सरकार

ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि आवंटित की है। दतिया और सतना हवाई अड्डों को शीघ्र लोकार्पित किया जाएगा। प्रदेश के धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़क और रेल यातायात के साथ विमानन सुविधाओं का विकास भी आवश्यक है। इस उद्देश्य से पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत वर्तमान में इंदौर, उज्जैन एवं ओंकारेश्वर को जोड़ा गया है।

- प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत बनाए रखने के प्रति मेरी सरकार गंभीर है। अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। नक्सल गतिविधियों पर अंकुश की स्थिति है। नक्सल उन्मूलन के लिए पर्याप्त बल उपलब्ध करवाकर गंभीरता से कार्य हो रहा है।
- मध्यप्रदेश में ई-समन की व्यवस्था देश में सर्वप्रथम लागू हुई है। नए कानून लागू होने के पश्चात समन की तामीली ऑनलाइन माध्यमों जैसे व्हाट्स-अप और ई-रक्षक ऐप के माध्यम से की जा रही है। मेरी सरकार इन नए कानूनों के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने प्रशासकीय पुनर्गठन आयोग का गठन किया है, जो जनहित में जिलों और तहसीलों के पुनर्गठन पर कार्य कर रहा है।

- प्रदेश में वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए और मालवाहनों के प्रदेश में निर्बाध परिवहन के लिए अहम निर्णय लेकर समस्त परिवहन चेकपोस्टों को बंद कर दिया और इसके स्थान पर नवीन वाहन चेकिंग मॉडल लागू किया गया। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में 45 "रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट" प्रारंभ कर दिए गए हैं।
- सुशासन के लिए मेरी सरकार ने ठोस प्रयास किए हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ नागरिकों को अधिसूचित सेवाएँ देने की कानूनी गारंटी दी गई है। इसके लिए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 25 सितम्बर 2010 से प्रभावशील है। लोकसेवा गारंटी के तहत करीब 10.95 करोड़ आवेदनों का निराकरण किया गया है। नागरिकों को एक दिन में सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा व्यवस्था" है। इसके तहत अब तक 2 करोड़ 83 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ हुआ है।
- प्रदेश में सायबर तहसील परियोजना को लागू किया गया है। सायबर तहसील के माध्यम से क्रय पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण कर ऑटोमेटिक की गई है। नामांतरण का आदेश एवं संशोधित खसरे/खतोनी की प्रतियाँ व्हाट्सएप और ई-मेल पर प्राप्त हो रही हैं। प्रदेश में लंबित

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के तीन राजस्व महाअभियान संचालित कर नामांतरण सीमांकन, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती आदि के एक करोड़ से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया।

- सदन को यह अवगत करवाते हुए हर्ष है कि मेरी सरकार ने दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में नागरिकों की समस्याओं को समय-सीमा में हल करने के लिए विशेष कार्यवाही की है। प्रदेश में 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान का संचालन कर 42 लाख से अधिक नागरिकों को हितलाभ प्रदान किए गए।
- प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। मेरी सरकार मध्यप्रदेश में इस मंत्र के क्रियान्वयन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जनकल्याण की किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया है। नए प्रकल्प भी क्रियान्वित हो रहे हैं। बहनों के सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण का दृढ संकल्प है।
- मेरी सरकार राज्य का पूर्ण विकास, नागरिकों की मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक उन्नति तथा प्रसन्नता से ही संभव मानती है। इस दिशा में राज्य आनंद संस्थान, विद्यार्थियों के

परिपूर्ण और आनंदमयी जीवन कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में मानवीय मूल्य की शिक्षा को "आनंद सभा कार्यक्रम" के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहा है।

- मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। मध्यप्रदेश की प्रगति में गत एक वर्ष में जो नए-नए आयाम जुड़े हैं वे गर्व करने के साथ ही ऐतिहासिक स्वरूप के भी हैं। कहा गया है कि अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ होता है, जिसके अनुभवों का लाभ लिया जाना चाहिए। वर्तमान को सुधारकर भविष्य को उज्जवल बनाने के प्रयत्न करना मेरी सरकार का दायित्व है। इस दायित्व को पूरा करने में मेरी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मेरी सरकार ने प्रदेश में कई नवाचार कर नागरिकों को प्रसन्न और सद्भाव, ज्ञानवृद्धि और परस्पर मेलजोल के अवसर दिलवाने के प्रयास भी किए हैं। मेरी सरकार प्रदेश में ऐसे वातावरण के निर्माण के लिए कार्य कर रही है, जो प्रत्येक नागरिक को विकास का लाभ पहुँचाकर उनके जीवन को माधुर्य के भाव से भर दे।

आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ

धन्यवाद ।

जय हिन्द - जय मध्यप्रदेश ।

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल-2025.